

**Examrace: Downloaded from examrace.com**

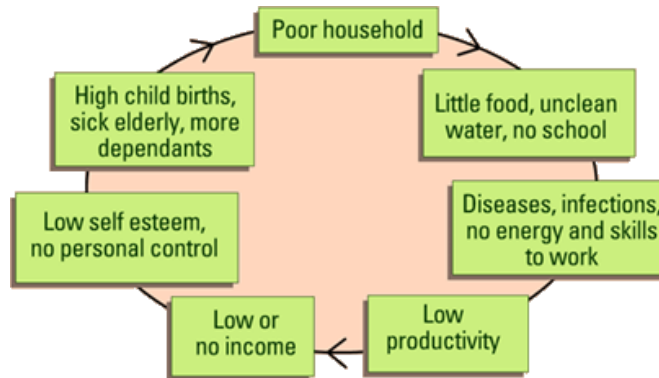
For solved question bank visit [doorsteptutor.com](http://doorsteptutor.com) and for free video lectures visit [Examrace YouTube Channel](#)

## एनसीईआरटी कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 4: गरीबी यूट्यूब व्याख्यान हैंडआउट्स for Competitive Exams

Get top class preparation for IAS right from your home: Get [detailed illustrated notes covering entire syllabus](#): point-by-point for high retention.

Get video tutorial on: [Examrace Hindi Channel at YouTube](#)

- प्रमुख चुनौतियां – गरीबी, बुनियादी ढांचे और विकास
- भारत – स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश के लिए उच्चतम मानव पूंजी – रोजगार बनाने का लक्ष्य
- उद्देश्य - बुनियादी जरूरतों को प्रदान करें और गरीबी को कम करें
- अंत्योदय (उत्थान गरीब लोगों का) – मुख्यधारा के लिए गरीबों को एकीकृत करें और सभी के लिए न्यूनतम जीवन स्तर
- अकेले भारत में 1/5 वें गरीब रहते हैं
- जवाहरलाल नेहरू - गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और असमानता खत्म



©Examrace. Report ©violations @<https://tips.fbi.gov/>

### गरीब कौन है?

- कच्चा घर
- कैलोरी का सेवन
- भुखमरी
- भूख
- साक्षरता की कमी
- सीमित आर्थिक अवसर
- अस्थिर रोजगार

- बीमार स्वास्थ्य और विकलांगता
- कुपोषण
- ब्याज की उच्च दर पर ऋण उधार लें - ऋणात्मकता
- बिजली तक पहुंच नहीं
- पाक कला ईंधन - लकड़ी है
- कोई सुरक्षित पेयजल नहीं
- लिंग असमानता
- मातृत्व के लिए कम देखभाल
- भूमिहीन मजदूरों और छोटे भूमि अधिग्रहण
- सड़कों पर स्व-रोजगार
- भविष्य का भय, शक्तिहीनता, प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता की कमी

### प्रमुख पहलु

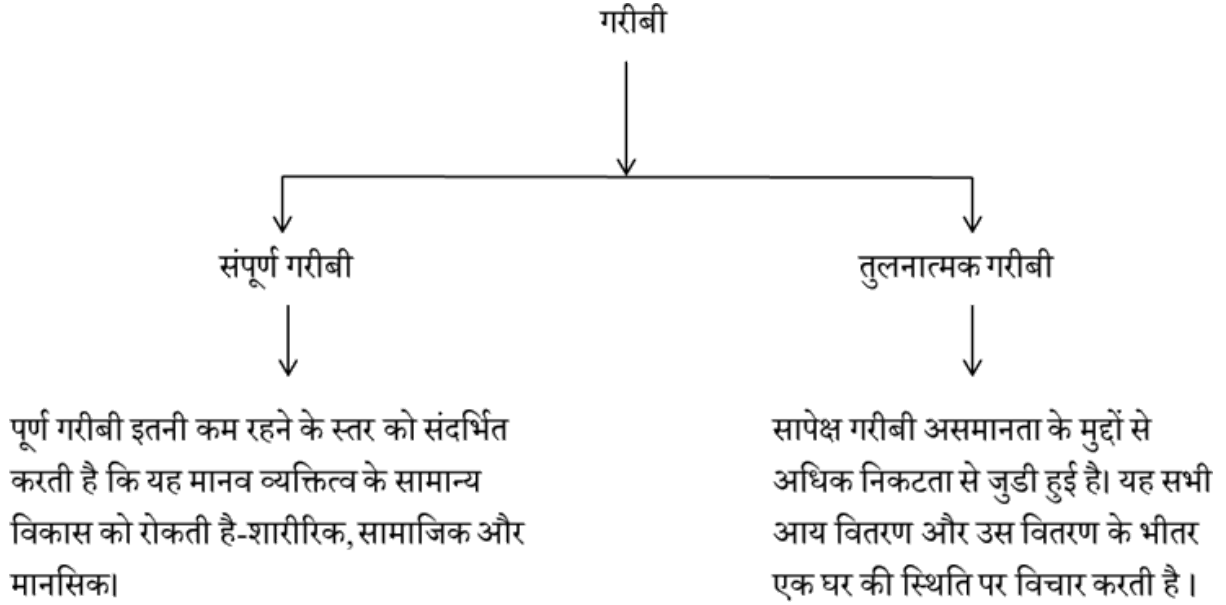
- कम पूंजी निर्माण
- बुनियादी ढांचे की कमी
- मांग की कमी
- जनसंख्या का दबाव
- सामाजिक / कल्याण जाल की कमी

### गरीब की पहचान

दादाभाई नौरोजी

- पहली बार गरीबी रेखा पर चर्चा की – कैदियों और मौजूदा कीमतों का मेनू “रहने की जेल लागत” के रूप में पहुंचने के लिए
- बच्चे जेलों में नहीं रहते हैं इसलिए उन्होंने समायोजित किया –  $1/3$  बच्चे के रूप में और उनमें से आधे बहुत कम खपत -  $(1/6)$  (शून्य) +  $(1/6)$  (आधा) +  $(2/3)$  (पूर्ण) =  $(3/4)$  (पूर्ण)
- रहने की वयस्क जेल लागत के  $3/4$  वें के रूप में औसत गरीबी रेखा दी
- 1962 - योजना आयोग अध्ययन समूह
- 1979 - ‘न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर कार्य बल’
- 1989 और 2005 - ‘विशेषज्ञ समूह’

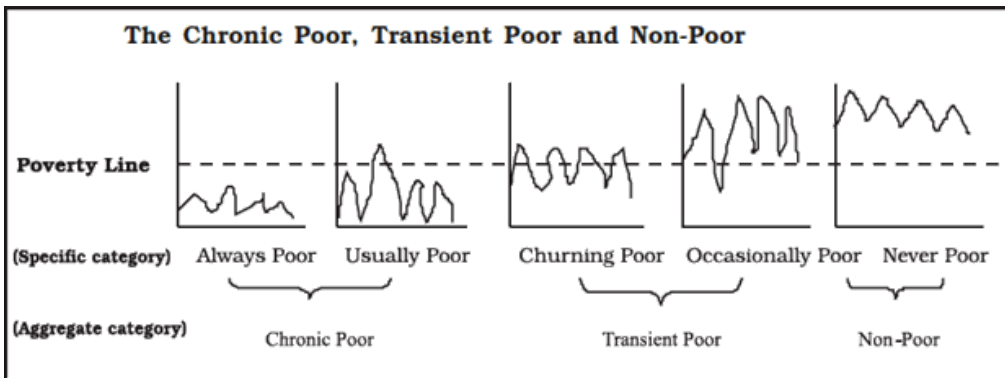
### गरीबी वर्गीकृत करना



[©Examrace. Report ©violations @https://tips.fbi.gov/](https://tips.fbi.gov/)



[©Examrace. Report ©violations @https://tips.fbi.gov/](https://tips.fbi.gov/)



[©Examrace. Report ©violations @https://tips.fbi.gov/](https://tips.fbi.gov/)

- गरीबों को मंथन करना - अंदर और बाहर जाना (छोटे किसान और मौसमी श्रमिक)
- कभी-कभी गरीब: अधिकांश समय में अमीर लेकिन कभी-कभी खराब भाग्य होता है।

## गरीबी रेखा

- न्यूनतम कैलोरी सेवन के मौद्रिक मूल्य (प्रति व्यक्ति खर्च) द्वारा ग्रामीण के लिए 2,400 कैलोरी थी और शहरी के लिए 2,100 (2009-10 के लिए ग्रामीण के लिए 673 रुपये और शहरी के लिए 860 रुपये)
- गरीबी से जुड़ी आमदनी के अलावा अन्य कारक – गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता
- विकास का उद्देश्य निरक्षरता, बीमारी, स्वास्थ्य, संसाधनों की कमी और राजनीतिक आजादी की कमी को दूर करना है। 1990 के आर्थिक सुधारों से गरीबी के स्तर में गिरावट आई।

## उपकरण

- अमर्त्य सेन ने उल्लेख किया कि नोबेल पुरस्कार विजेता सेन सूची विकसित हुई।
- गरीबी गैप सूची
- वर्गीय गरीबी गैप



## गरीबों की संख्या

- मुख्य गणना अनुपात: बीपीएल के लोगों की तुलना के रूप में अनुमानित गरीबों की संख्या। गंभीरता को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- गरीबी गैप अनुपात: गैप जिसका अर्थ है कि गरीब बीपीएल का उपयोग गरीबी रेखा से कम होता है। गरीबी की गंभीरता को दर्शाता है।
- अनुपात और प्रतिशत के संदर्भ में
- योजना आयोग द्वारा गरीबी पर आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक किए गए – एनएसएसओ द्वारा एकत्रित उपभोग व्यय डेटा के आधार पर
- 1973 - 74: 320 दस लाख बीपीएल (55 % बीपीएल था - ग्रामीण में 80 %)
- 2011 - 12: 270 दस लाख बीपीएल (20 % बीपीएल था - ग्रामीण में 80 %)
- 1973 - 74 - तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में गरीबों का एक बड़ा हिस्सा था
- 1973 से 2012 के दौरान - ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय गरीबी स्तर से काफी दूर हैं

## गरीबी के कारण

- संस्थागत और सामाजिक कारक
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता
- सामाजिक बहिष्कार
- बेरोजगारी
- ऋणग्रस्तता
- धन का असमान वितरण
- औपनिवेशिक अतीत
- सीमित साधन
- कमजोर संस्थानों
- भ्रष्टाचार
- जन संख्या विसफोट

कुल गरीबी व्यक्तिगत गरीबी का योग है।

ब्रिटिश शासन – अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर के पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा; विऔद्योगीकरण, करों में वृद्धि, खाद्यान्नों के निर्यात, 26 मिलियन लोगों की मौत बी / डब्ल्यू 1875 से हुई और 1900, ब्रिटिश सेनाओं के लिए जनशक्ति के रूप में भारत और भारतीयों में ब्रिटिश सामानों के लिए बाजार बनाते हैं।

आज - कृषि महत्वपूर्ण है, भूमि का स्वामित्व बहुत महत्वपूर्ण है - 1947 के बाद भूमि का पुनर्विभाजन

ग्रामीण भारत – छोटे किसान, कम उपजाऊ, बारिश निर्भर, निर्वाह फसल और पशुधन, ऋण वापस भुगतान करने में असमर्थता और भूमि का विखंडन, एसटी / एससी रोजगार में भाग लेने में असमर्थ है

शहरी भारत – ग्रामीण गरीबों का अतिप्रवाह जो शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है, आकस्मिक मजदूर (सबसे कमजोर) ऋण और माल की कीमत में वृद्धि

2 अलग-अलग समूह: जिनके पास उत्पादन का साधन है और अच्छी आय अर्जित करें और जिनके पास अस्तित्व के लिए व्यापार करने के लिए केवल श्रम है।

## नीतियां और कार्यक्रम

- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951 - 56) - आर्थिकता लाने का आग्रह और सामाजिक परिवर्तन वर्तमान परिस्थितियों में गरीबी के तथ्य से आता है और आमदनीमें असमानताओं, धन और अवसर

- द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956 - 61) - आर्थिक विकास के लाभ को अधिक अर्जित करना होगा और अपेक्षाकृत अधिक समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग - गरीबी निवारण
- **गरीबी में कमी के दृष्टिकोण**
- **पहला दृष्टिकोण - विकास उन्मुख दृष्टिकोण:** उम्मीद के आधार पर हु आ आर्थिक विकास का प्रभाव - सकल घरेलू उत्पाद और पीसीआई में तेजी से वृद्धि समाज के सभी वर्गों में फैल जाएगी और गरीब वर्गों के लिए उलझ जाएगी - 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में मुख्य केंद्र-बिंदु। तेजी से औद्योगिक विकास से लाभ और कृषि का परिवर्तन हरित क्रांति के माध्यम से होगा (यह असमानताओं में वृद्धि हुई)
- **दूसरा दृष्टिकोण - तीसरी 5 साल की योजना:** अतिरिक्त संपत्ति बनाएं और गरीबी उन्मूलन से काम पीढ़ी के साधन कार्यक्रम - स्व-रोजगार का विस्तार करें और मजदूरी रोजगार - ग्रामीण रोजगार जनरेशन प्रोग्राम (आरईजीपी) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरई) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को एसजेएसआरई के रूप में पुनर्गठित किया गया है। एक समान कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी गरीबों के लिए आजीविका मिशन भी किया गया है।
- अगस्त 2005 में, नया अधिनियम गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए पारित किया हर ग्रामीण परिवार के लिए जिसके वयस्क स्वयंसेवक को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए अकुशल शारीरिक श्रम करना है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
- अधिकारी बीमारी प्रेरित हैं, अपर्याप्त प्रशिक्षित, भ्रष्टाचार का खतरा और विविधता से दबाव के लिए कमजोर स्थानीय अभिजात वर्ग के, संसाधन अक्षम हैं जिसको इस्तेमाल किया और बर्बाद किया। कार्यक्रम कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर के संस्थानों की गैर-भागीदारी भी है।
- **तीसरा दृष्टिकोण: गरीबों के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं** - रियायती शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता - रोजगार के अवसर पैदा करें
- भोजन और पोषण की स्थिति में सुधार करें - पीडीएस, एकीकृत बाल विकास योजना और मध्याह्न भोजन योजना
- बुनियादी ढांचा और आवास - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना
- सामाजिक सुरक्षा - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - बेसहारा और विधवाओं के लिए पेंशन
- आर्थिक समावेश - जन धन योजना - प्रत्येक बैंक खाताधारक हकदार है रु. 1 लाख दुर्घटना बीमा और रु. 30,000 जीवन बीमा कवर।
- स्वास्थ्य - आयुषमान भारत

## मामले का अध्ययन

- सर्जुजा में आदिवासियों का 55 % बहुमत है, भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक और पहाड़ी या हिल कोरवास सरकार द्वारा एक प्राचीन जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है, नीचे 5 % में गिर जाते हैं।
- कपास किसान: 2002 में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र 8,300 हेक्टेयर है - 03 दुनिया में कपास की खेती के अंतर्गत। प्रति हेक्टेयर 300 किलो की कम उपज। यह उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। किसानों को परेशान उच्च उत्पादन लागत के कारण, कम और अस्थिर उपज, दुनिया की कीमतों में गिरावट, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सब्सिडी की वजह से उत्पादन में वैश्विक भरमार, और मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वैश्वीकरण के कारण घरेलू बाजार खोलना।
- किसान आत्महत्या के कारण:
  - तकनीकी सहायता के बिना पारंपरिक से एचवाईवी फसलों में स्थान बदलना
  - कृषि में सार्वजनिक निवेश में गिरावट
  - बड़े वैश्विक फर्मों द्वारा बीज के अंकुरण का कम दर
  - फसल बरबाद, कीट का हमला और अनावृष्टि
  - निजी धन उधारदाताओं से 36 % से 120 % की उच्च ब्याज दर पर ऋण
  - सस्ता आयात मूल्य निर्धारण में गिरावट का कारण बनता है
  - फसलों के लिए पानी तक पहुंच की कमी - उन्हें पैसे उधार लेने के लिए मजबूर किया

## गरीबों के अनुमान पर सांभतेयां

- सुरेश तेंदुलकर समिति कैलोरी सेवन पर आधारित है। जिसमें यह गरीबी को कम करने के लिए आधा एमडीजी में दिए गए द्वारा करने के उद्देश्य से किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2004 - 2005 से 2009 - 10 के बाद गरीबी को प्रति वर्ष 1.5 % कम कर दिया गया है।
- डॉ एन सी सक्सेना समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना का आयोजन किया। इसमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त अनुभागों का स्वतः बहिष्कार है और कुछ वंचित के स्वचालित समावेशन और समाज के कमजोर वर्ग। यह आबादी का 50 % से अधिक अनुमान लगाया गया गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले।
- एसआर हसीम समिति ने शहरी गरीबों की पहचान करने का सुझाव दिया। यदि किसी भाग में रेफ्रिजरेटर, दो व्हीलर, लैंडलाइन टेलीफोन या वॉशिंग मशीन जैसी चीजें हैं तो उन्हें गरीब के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि हाल के दशक में शहरी गरीबी कम हो गई है।
- सी रंगराजन समिति - ग्रामीण में 32 रुपये वाले व्यक्ति और शहरी में 47 रुपये गरीब श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। उनका अनुमान खरीद शक्ति समता (पीपीपी) पर आधारित है। उनकी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों में गरीबी में गिरावट से 39.6 % से 30.9 % की गिरावट आई है और 35.1 % से 20.4 %

-Manishika

Developed by: [Mindsprite Solutions](#)